कैंसर दवा को यूएसएफडीए की मंजूरी

जेनेरिक दवाओं के लिए आए 487 आवेदन में से 427 को मिली मंजूरी

अहमदाबाद, 14 नवंबर भारत का दवा उद्योग दुनिया भर में अपनी गुणवत्ता और तेजी से विकसित होती तकनीक के लिए पहचाना जाता है. इस क्षमता का एक और बड़ा प्रमाण शुक्रवार को देखने को मिला, जब अहमदाबाद की प्रमुख दवा निर्माता कंपनी जायडस को अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (यूएसएफडीए) से एक महत्वपूर्ण मंजूरी प्राप्त हुई.

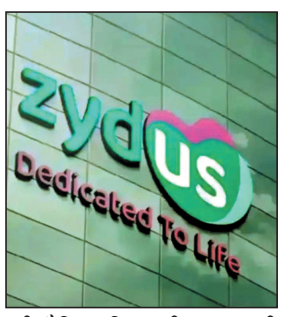

कंपनी की वह दवा, जो प्रोस्टेट कैंसर के इलाज में प्रभावी मानी जाती है, अब अमेरिकी बाजार में उपलब्ध हो सकेगी. यह मंजूरी न केवल जायडस के लिए व्यावसायिक विस्तार का अवसर है, बल्कि भारतीय फार्मा सेक्टर की वैश्विक विश्वसनीयता का भी प्रतीक है. अमेरिका जैसे सख्त नियामक मानकों वाले बाजार में स्वीकृति मिलना किसी भी दवा कंपनी के लिए बड़ी उपलब्धि होती है. खास बात यह है कि इस इंजेक्शन का उत्पादन गुजरात के अहमदाबाद स्थित सेज विनिर्माण इकाई में किया जाएगा, जिससे देश के भीतर ही उच्च गुणवत्ता वाली निर्यातङ्गउन्मुख दवाओं का निर्माण संभव होगा.

> कंपनी के मुताबिक, यह इंजेक्शन विशेष रूप से प्रोस्टेट कैंसर के इलाज में उपयोग होता है और वर्तमान में इसकी वार्षिक बिक्री अमेरिका में लगभग 6.9 करोड़ डॉलर की है. मंजूरी मिलते ही जायडस अब इस बाजार में अपनी हिस्सेदारी मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाएगी. दवा का उत्पादन अहमदाबाद के विशेष आर्थिक जोन (स्र्शं) स्थित अत्याधुनिक संयंत्र में किया जाएगा, जहां गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखा जाता है.

जायडस पहले से ही अमेरिकी बाजार में मजबूत उपस्थिति रखती है और 30 सितंबर 2025 तक 487 जेनरिक दवाओं के लिए आवेदन कर चुकी है, जिनमें से 427 को मंजूरी प्राप्त हो चुकी है. यह नया कदम कंपनी की वैश्विक रणनीति को और मजबूती देने वाला साबित हो सकता है. भारतीय दवा निर्माता जायडस को शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली जब उसकी कैंसर उपचार में उपयोग की जाने वाली दवा ल्युप्रोलाइड एसिटेट इंजेक्शन को अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (यूएसएफडीए) की अंतिम मंजूरी प्रदान की गई.

20 वर्षों में आयात बिल में 15 गुना बढ़ोतरी

नई दिल्ली, 14 नवंबर. देश में खाद्य तेलों की खपत लगातार बढ़ रही है और घरेलू उत्पादन इस मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं है. इसका सीधा असर आयात पर दिख रहा है, जो 2024-25 के विपणन वर्ष में छलांग मारकर 1.6 करोड़ टन पहुंच गया. सॉल्वेंट एक्स्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसईए) द्वारा जारी ताजा रिपोर्ट बताती है कि इस बढ़ते आयात पर भारत को 1.61 लाख करोड़ रुपये खर्च करने पड़े हैं— जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 22 प्रतिशत अधिक है. पिछले 20 वर्षों में खाद्य तेल आयात की मात्रा 2.2 गुना और लागत लगभग 15 गुना बढ़ चुकी है, जो खपत आधारित अर्थव्यवस्था में बढ़ती निर्भरता का स्पष्ट संकेत है. भारत दुनिया के सबसे बड़े खाद्य तेल आयातकों में शामिल है.

प्रदूषण नियंत्रण के लिए तैयार दिल्ली सरकार

तेहखंड और तुगलकाबाद गांव में निरीक्षण और दिशा-निर्देश

सार्वजनिक परिवहन किया जा रहा है ईवी में तब्दील : रेखा गुप्ता

नयी दिल्ली, 14 नवंबर. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए उनकी सरकार सार्वजनिक परिवहन को तेजी से ईवी मोड में बदल रही है. गुप्ता ने आज यहां तेहखंड स्थित दिल्ली परिवहन निगम डिपो में स्वचालित परीक्षण स्टेशन परियोजना का शिलान्यास किया और 50 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर जनता की सेवा में समर्पित किया.

उन्होंने कहा कि दिल्ली का यह दूसरा बड़ा ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटर मार्च तक पूरा हो जाएगा जहां लगभग 72,000 वाहनों की वार्षिक टेस्टिंग की अत्याधुनिक व्यवस्था होगी. इससे वाहन फिटनेस की प्रक्रिया और अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और तकनीक-आधारित बनेगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिल्ली सरकार सार्वजनिक परिवहन को तेजी से ईवी मोड में बदल रही है. आज डीटीसी के बेड़े में 50 नई ईवी बसें शामिल होना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है.

> उन्होंने कहा कि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए उनकी सरकार हर मोर्चे पर काम कर रही है. कूड़े के पहाड़ों को हटाया जा रहा है और सफाई अभियानों को युद्धस्तर पर चलाया जा रहा है. इसमें धूल नियंत्रण, मैकेनिकल स्वीपिंग और वॉटर स्प्रिंकलिंग को तेज किया गया है. इसके अलावा दिल्ली को हरा-भरा बनाने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं. उन्होंने तेहखंड और तुगलकाबाद गांव का दौरा कर कचरा प्रबंधन, नालियों की सफाई, सड़क निर्माण और स्वच्छता से जुड़े कार्यों की विस्तृत समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और सतत निगरानी के साथ पूरे हों ताकि स्थानीय निवासियों को तुरंत राहत मिल सके और समस्याओं की पुनरावृत्ति न हो.

थोक मुद्रास्फीति की दर घटकर शून्य से हुई 1.21 प्रतिशत

खाद्य मूल्य में 5.04 प्रतिशत तक की भारी गिरावट देखी गई

थोक महंगाई दर शून्य से नीचे दर्ज की गई

नयी दिल्ली, 14 नवंबर भारत में थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति की दर अक्टूबर में अचानक माइनस जोन में चली गई है. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, मुद्रास्फीति -1.21प्रतिशत दर्ज की गई. यह गिरावट मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों, कच्चे तेल, बिजली और बुनियादी धातुओं की कीमतों में उल्लेखनीय कमी के चलते हुई है.

खासतौर पर खाद्य मूल्य में 5.04 प्रतिशत तक की भारी गिरावट देखी गई. सब्जियाँ लगभग 35 प्रतिशत, प्याज 65प्रतिशत और आलू 40 प्रतिशत सस्ते हो गए हैं. इस मंदी के पीछे जीएसटी में हाल ही में की गई कटौती का बड़ा हाथ है, क्योंकि कई दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर कर 0 प्रतिशत या 5 प्रतिशत तक घटा दिए गए हैं.

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में हाल में किये गये बदलावों के कारण थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति की दर अक्टूबर में घटकर शून्य से 1.21 प्रतिशत नीचे दर्ज की गयी. इससे पहले सितंबर में यह 0.13 प्रतिशत और अगस्त में 0.52 प्रतिशत पर रही थी जबकि उससे पहले लगातार दो महीने शून्य से नीचे रही थी.

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, खाद्य पदार्थों, कच्चा तेल एवं प्राकृतिक गैस, बिजली, खनिज तेल और बुनियादी धातुओं के विनिर्माण में पिछले साल अक्टूबर की तुलना में इस साल अक्टूबर में कीमतों में गिरावट के कारण थोक महंगाई दर शून्य से नीचे दर्ज की गयी है. तशत नीचे रही. इसका मुख्य कारण इस साल 22 सितंबर से जीएसटी के तहत करों की दरों में कटौती रही. अधिकतर खाद्य पदार्थों पर कर शून्य या पांच प्रतिशत कर दी गयी.

> अक्टूबर में एक साल पहले के मुकाबले हरी सब्जियां 35 प्रतिशत, आलू 40 प्रतिशत और प्याज 65 प्रतिशत सस्ता हुआ. दालों के दाम 16 फीसदी और फलों के सात फीसदी घटे. ईंधन एवं ऊर्जा वर्ग में रसोई गैस सिलेंडर 9.5 प्रतिशत, पेट्रोल के 2.6 प्रतिशत और डीजल के 1.9 प्रतिशत घट गये. इससे पहले, 12 नवंबर को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर में खुदरा महंगाई की दर भी घटकर 0.25 प्रतिशत पर रह गयी थी.

फ्लिपकार्ट विक्रेताओं से नहीं लेगी कमीशन

बेंगलुरु, 14 नवंबर घरेलू ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट ने 1,000 रुपये से कम कीमत के उत्पादों के लिए विक्रेताओं से कोई कमीशन नहीं लेने की घोषणा की है जिससे ग्राहकों के लिए इनकी कीमत कम होने की उम्मीद है. ऑनलाइन बिक्री को ज्यादा समावेशी एवं विकास आधारित बनाने की प्रतिबद्धता के अनुरूप जीरो कमीशन मॉडल की शुरुआत की गयी है. इससे लागत की व्यवस्था सरल बनेगी, प्रतिस्पर्धी कीमतों को बढ़ावा मिलेगा. इसके तहत शॉप्सी पर सभी उत्पादों पर शून्य कमीशन लागू किया गया है. इससे ग्राहकों के लिए उत्पाद ज्यादा किफायती बनेंगे. जीरो कमीशन मॉडल को इस तरह से डिजाइन किया गया है जिससे स्थानीय एवं उभरते एमएसएमई ब्रांड डिजिटल इकोनॉमी से जुड़ सकें.

भारतीय शेयर बाजार में आई तेजी

592 अंक की बढ़त पर रहा सेंसेक्स

11 अंक से आगे रहा निफ्टी

मुंबई, 14 नवंबर. विदेशों से मिले नकारात्मक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजारों में शुक्रवार को लगातार पांचवें दिन तेजी रही और प्रमुख सूचकांक हरे निशान में बंद हुए. खास बात यह रही कि प्रमुख सूचकांक लगभग पूरे दिन गिरावट में रहने के बाद आखिरी आधे घंटे के कारोबार में अचानक उछलते हुए हरे निशान में बंद हुआ.

बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स दोपहर 2.57 बजे 84,098.29 अंक पर था और 12 मिनट में 592 अंक उछलकर 84,690.55 अंक पर पहुंच गया. आखिर में यह पिछले कारोबारी दिवस (84,478.67 अंक) के मुकाबले 84.11 अंक (0.10 प्रतिशत) ऊपर 84,562.78 अंक पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी-50 सूचकांक भी पूरे दिन की गिरावट के बाद अंत में 30.90 अंक यानी 0.12 प्रतिशत चढ़कर 25,910.05 अंक पर पहुंच गया. मझौली और छोटी कंपनियों में भी तेजी रही. निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 0.11 फीसदी और स्मॉलकैप-100 सूचकांक 0.38 अंक की बढ़त में रहा. एनएसई में कुल 3,188 कंपनियों के शेयरों में कारोबार हुआ.

> सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से 19 के शेयर हरे निशान में और अन्य 11 के लाल निशान में बंद हुए. इटरनल में सबसे अधिक 1.97 प्रतिशत, बीईएल में 1.70, ट्रेंट में 1.57, एक्सिस बैंक में 1.46, भारतीय स्टेट बैंक में 1.34, बजाज फाइनेंस में 1.30 और सनफार्मा में 1.19 फीसदी की तेजी रही. इनके अलावा एशियन पेंट्स, अडानी पोर्ट्स, हिंदुस्तान यूनीलिवर, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईटीसी और पावर ग्रिड के शेयर भी बढ़त में रहे. इंफोसिस का शेयर सर्वाधिक 2.58 प्रतिशत टूटा.

ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की नायडू ने रखी आधारशिला

नयी दिल्ली, 14 नवंबर. केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के साथ मिल कर आंध्र प्रदेश में कुरनूल में ड्रोन सिटी और हरिकोटा में स्पेस सिटी परियोजनाओं की शुक्रवार को आधारशिला रखी.

गोयल ने विशाखापत्तनम में 30वें सीआईआई साझेदारी शिखर सम्मेलन के अवसर पर वर्चुअल माध्यम से आयोजित शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि संयुक्त आंध्र प्रदेश और पूरे देश के स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी के विकास में मुख्यमंत्री श्री नायडू का योगदान सराहनीय है. गोयल ने कहा कि श्री नायडू ने कुरनूल के निकट ओर्वाकल औद्योगिक नोड में लगभग 300 एकड़ में ड्रोन विनिर्माण इकाइयों के लिए अलग से ड्रोन सिटी बनाने का फैसला कर तकनीकी विकास के क्षेत्र में अपने इसी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया है.

यह देश में पहली ड्रोन सिटी होगी. मंत्री ने ड्रोन के प्रभावी उपयोग और ऑपरेशन सिंदूर में उनकी भूमिका का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि भारत को उच्च गुणवत्ता वाले ड्रोन के उत्पादन में आत्मनिर्भर होना चाहिए और कुरनूल में बनने वाला ड्रोन सिटी इस दिशा में मददगार होगा. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने श्रीहरिकोटा के निकट एक स्पेस सिटी के निर्माण की पहल की भी सराहना की, जो भारतीय रॉकेट प्रक्षेपण का केंद्र है.

सोना-चांदी की कीमत में गिरावट

सोने में 1,126 और चांदी में 2,074 की कमी

नई दिल्ली: 14 नवंबर सोने-चांदी की कीमतों में लगातार बदलाव निवेशकों और खरीदारों के लिए अहम जानकारी बन गई है. शुक्रवार को सोने और चांदी के दाम में गिरावट दर्ज की गई है. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार, 10 ग्राम सोना आज 1,26,554 से 1,25,428 पर आ गया है, जबकि चांदी 2,074 गिरकर 1,60,656 प्रति किलो पर पहुंच गई है.

इस साल सोने की कीमतों में कुल 49,266 की वृद्धि हुई है, वहीं चांदी की कीमतों में 74,639 का इजाफा हुआ है.

सोने और चांदी के दाम न सिर्फ वैश्विक बाजार से प्रभावित होते हैं, बल्कि शहर और राज्य के अनुसार भी अलग-अलग होते हैं. इसका कारण ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, लोकल ज्वेलरी एसोसिएशन की नीति और खपत की मात्रा है. खरीदारों को सलाह दी जाती है कि हमेशा हॉलमार्क वाला प्रमाणित सोना ही खरीदें और खरीदारी से पहले कीमत क्रॉस-चेक करें.

बिजली 2.89% महंगी

नई दिल्ली, 14 नवंबर. देश की थोक महंगाई अक्टूबर 2025 में और नीचे फिसली है. वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार डब्ल्यूपीआई आधारित महंगाई दर (-)1.21 प्रतिशत रही, जो सितंबर से भी कम है. खाद्य पदार्थों, कच्चे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, धातुओं और बिजली के दाम में नरमी ने कुल इंडेक्स को नीचे खींचा. ऊर्जा कीमतों में 3.13 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जबकि ईंधन और बिजली समूह 1.12 प्रतिशत बढ़ा. विनिर्मित उत्पादों में हल्की कमी से भी महंगाई नीचे रही. लगातार चार महीने से थोक महंगाई नकारात्मक रहने से अर्थव्यवस्था पर दबाव कम हुआ है.

यात्री वाहनों की बिक्री 17.2 प्रतिशत बढ़ी

त्योहारी मांग और जीएसटी दरों में कटौती के कारण बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर

नयी दिल्ली, 14 नवंबर. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में नयी पीढ़ी के सुधारों के बाद अक्टूबर में घरेलू बाजार में यात्री वाहनों की थोक बिक्री 17.2 प्रतिशत बढ़कर 4,60,739 इकाई के नये रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गयी. यात्री वाहनों में कारों, उपयोगी वाहनों और वैन को शामिल किया जाता है.

पिछले साल अक्टूबर में इनकी बिक्री 3,93,238 इकाई रही थी. दुपहिया और तिपहिया की बिक्री ने भी नया रिकॉर्ड बनाया. वाहन निर्माता कंपनियों के संगठन सियाम के शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर में तिपहिया की बिक्री में सालाना आधार पर 5.9 प्रतिशत और दुपहिया की बिक्री में 2.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई. कुल 81,288 तिपहिया और 22,10,727 दुपहिया वाहन बिके. सियाम के निदेशक राजेश मेनन ने इन आंकड़ों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अक्टूबर में यात्री वाहनों, दुपहिया और तिपहिया की मासिक बिक्री ने नया रिकॉर्ड बनाया.

समाचार विशेष

कांग्रेस की तिकड़ी के सिर बंधा चुनाव का सेहरा!

उत्तराखंड : अध्यक्ष बने गोदियाल तो प्रीतम सिंह और हरक सिंह को चुनावी कमान

देहरादून. कांग्रेस आलाकमान ने कुछ ऐसा किया है जो अमूमन पार्टी के प्रचलित नेचर से अलग है. मंगलवार को जब पार्टी के बड़े नेता बिहार चुनाव की समीक्षा में उलझे थे, तब उत्तराखंड में खेल हो गया. राज्य विधानसभा चुनाव में अभी करीब सवा साल बचा है.

इससे पहले मंगलवार शाम को कांग्रेस ने चुनाव मोड में आने की खुली घोषणा कर दी है. पार्टी ने चुनाव में प्रचार प्रमुख की जिम्मेदारी पूर्व अध्यक्ष और मंत्री रहे प्रीतम सिंह को दी है तो चुनाव मैनेजमेंट की जिम्मेदारी सीबीआई की जांच का सामना कर रहे हरक सिंह रावत को दी है. ये ही नहीं, पार्टी अध्यक्ष का ताज अब गणेश गोदियाल को पहनाया गया है, जो गढ़वाल की राजनीति में खासे सक्रिय हैं. खास बात ये है कि उत्तराखंड में कांग्रेस राजनीति की धुरी रहे वेटरन नेता हरीश रावत को कोई भूमिका नहीं दी गई, जबकि पिछले विधानसभा चुनाव से पहले वो कैंपेन कमेटी के सरपरस्त बनाए गए थे.

उत्तराखंड में लगातार दो विधानसभा चुनाव हारने और तीन लोकसभा चुनावों में एक भी सीट ना जीतने वाली कांग्रेस के लिए 2027 का विधानसभा चुनाव करो या मरो वाला है. जानकर कहते हैं कि पार्टी ने आउटगोइंग अध्यक्ष करण मेहरा को रिप्लेस करके ये संदेश देने की कोशिश की है कि पार्टी नया नेतृत्व और नए एक्सपेरिमेंट की हिमायती है.

> **हरीश रावत को दरकिनार करना ठीक नहीं**
>
> दिलचस्प पहलू ये भी है कि कांग्रेस में पूर्व सीएम हरीश रावत बेशक किसी भूमिका में नहीं आ पाए हों, लेकिन उत्तराखंड की राजनीति में उनका कद छोटा नहीं है. जहां कुछ नेता हरीश रावत के रोल को दरकिनार करने को ठीक मानते हैं, वहीं एक वर्ग ऐसा है जो कहता है रावत बेशक उम्रदराज हों पर वो चूके नहीं हैं. पार्टी आलाकमान को उन्हें कम आंकने की गलती नहीं करनी चाहिए. कांग्रेस ने नए नेतृत्व के साथ ही 27 जिला अध्यक्षों का भी मनोनयन किया है.

आखिर बबुआ की उड़ीसा में क्यों बढ़ी रुचि!

लखनऊ. उड़ीसा दौरे के माध्यम से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव किन राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करने में लगे हुए हैं? उन्होंने उड़ीसा की राजनीति में अचानक रुचि क्यों बढ़ा दी है?

सपा मुखिया उड़ीसा में नौपाड़ा विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रमाकांत हाती के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के अलावा किन राजनीतिक मकसद को हासिल करना चाहते हैं? बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार के बाद सीधे अखिलेश यादव उड़ीसा में प्रचार के लिए निकल गए. वह उड़ीसा में हो रहे हैं विधानसभा उपचुनाव में अपने प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं. उन्होंने उड़ीसा में भी पीडीए का परचम ही उठाने के मकसद से इस सफर को किया है. अखिलेश यादव चाहते हैं कि उनकी पार्टी का विस्तार दूसरे राज्यों में भी हो. इसलिए पिछले कुछ सालों में उन्होंने मध्य प्रदेश ,महाराष्ट्र ,उड़ीसा ,पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तराखंड का भी ताबड़तोड़ दौरा किया है.

अब भाजपा का नया टारगेट बीएमसी चुनाव

मुंबई. बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न होते ही भारतीय जनता पार्टी ने अब अपनी राजनीतिक नज़रें मुंबई की सबसे बड़ी स्थानीय निकाय संस्था बृहन्मुंबई नगर निगम पर टिका दी हैं.

केंद्र और राज्य दोनों जगह सत्ता में काबिज भाजपा ने यहां संगठनात्मक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया है. इससे यह साफ है कि पार्टी ने अब 2026 के मुंबई मिशन की तैयारियां तेज कर दी हैं. भाजपा ने मुंबई इकाई में चार नए महासचिवों की नियुक्ति की है राजेश शिरवाडकर, गणेश खापरकर, आचार्य पवन त्रिपाठी और श्वेता पारुलेकर. इन नियुक्तियों की घोषणा मुंबई भाजपा अध्यक्ष और विधायक अमीत साटम ने की. माना जा रहा है कि यह बदलाव पार्टी के बूथ-स्तर के नेटवर्क को मजबूत करने और विपक्षी एकता को चुनौती देने की रणनीति का हिस्सा है.

जनवरी 2026 में बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनाव होने वाले हैं. राज्य का सत्तारूढ़ गठबंधन महा-यूति (भाजपा, शिंदे शिवसेना, एनसीपी अजित पवार गुट) इसे मिलकर लड़ने की तैयारी कर रहा है. वहीं विपक्षी महा विकास आघाड़ी (शिवसेना ठाकरे गुट, कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार गुट) में एकता की कमी साफ झलक रही है. हाल ही में महाराष्ट्र कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी बीएमसी चुनाव अपने दम पर

भाजपा की रणनीति : ग्राउंड पर पकड़ और गठबंधन समीकरण

बीजेपी की ओर से किए गए नए संगठनात्मक बदलाव का मकसद मुंबई में स्थानीय स्तर पर संगठन को धार देना है. पार्टी चाहती है कि 2026 के चुनाव में न सिर्फ शिवसेना (शिंदे गुट) और एनसीपी (अजित पवार गुट) के साथ तालमेल मजबूत रहे, बल्कि बीजेपी का अपना वोट बैंक भी पूरी तरह सक्रिय हो. विशेषज्ञ मानते हैं कि मुंबई में बीएमसी पर कब्जा पाना भाजपा के लिए राजनीतिक प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है. 2022 में चुनाव स्थगित होने के बाद अब 2026 के चुनाव में भाजपा पूरी ताकत झोंकने के मूड में है.

विशेष | **नगराध्यक्ष पदों पर आरक्षण से बदला राजनीतिक गणित**

निकाय चुनाव में महिलाओं की बढ़ी ताकत

चंद्रपुर. जिले में 10 नगर पालिकाओं और एक नगर पंचायत के आम चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है. नामांकन की अंतिम तारीख 17 नवंबर होने से नगराध्यक्ष और नगरसेवकों के चयन के लिए राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं के साथ बैठकों का दौर शुरू है. चुनावी दंगल शुरू हो चुका है.

सभी निगाहें नगराध्यक्ष पद के दावेदारों से लेकर अपने अपने प्रभाग में कौन कौन चुनाव मैदान में खडे है इस बात को लेकर लोगों में उत्सुकता चरम पर है. चंद्रपुर जिले में 10 नगर पालिकाओं और एक नगर पंचायत के लिए चुनाव हो रहे है. कुल 133 प्रभागों में 253 पार्षद होंगे. 371537 मतदाताओं में 184387 महिला और 187139 पुरूष और 11 अन्य मतदाता है. बल्लारपुर, वरोरा, मूल, घुग्घुस, चिमूर नगर पालिकाओं में महिला राज होगा.

महिला मतदाता ज्यादा- वरोरा, मूल, राजुरा, नागभीड़, चिमूर इन नगर पालिकाओं में पुरूषों के मुकाबले महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है. बल्लारपुर नगर पालिका में कुल 17 प्रभाग में 34 नगरसेवक चुने जाएंगे. यहां कुल 83821 मतदाता है जिसमें 41754 महिला और 42066 पुरूष एवं 8 अन्य मतदाता है. नगराध्यक्ष पद ओबीसी महिला के लिए आरक्षित है. भद्रावती में 14 प्रभाग में 29 नगरसेवक चुने जाएंगे. कुल मतदाता 52572 है. जिसमें 26015 महिला और 26557 पुरूष मतदाता है. यहां ओबीसी सामान्य नगराध्यक्ष होगा. वरोरा नगर पालिका में 13 प्रभाग में 27 नगरसेवक होंगे. कुल 43329 मतदाता है जिसमें 21826 महिला और 21499 पुरूष मतदाता है अन्य 4 है. यहां ओबीसी महिला के लिए नगराध्यक्ष पद आरक्षित है. ब्रम्हपुरी नगर पालिका में 11 प्रभाग में 23 नगरसेवक होंगे. कुल मतदाता 33779 है. जिसमें 16431 महिला और 17348 पुरूष मतदाता है यहां ओबीसी सामान्य के लिए नगराध्यक्ष पद आरक्षित है.

मूल-राजूरा में भी महिला वोटरों का दबदबा- मूल नगर पालिका में 10 प्रभाग में 20 नगरसेवक होंगे. कुल 21745 मतदाताओं में से 11108 महिला और 10636 पुरूष और एक अन्य मतदाता है. यहां ओबीसी महिला के लिए नगराध्यक्ष पद आरक्षित है.

> **चिमूर नपा में 10 प्रभाग में 20 पार्षद**
>
> गडचांदूर नगर पालिका में 10 प्रभाग में 20 पार्षद होंगे. 24457 मतदाताओं से 11557 महिला और 12900 पुरूष मतदाता है. यहां ओपन के लिए नगराध्यक्ष पद आरक्षित है. नागभीड़ नगर पालिका में 10 प्रभाग में 20 पार्षद होंगे. 20992 मतदाताओं 10749 महिला और 10243 पुरूष मतदाता होंगे यहां अनुसूचित जाति सामान्य के लिए नगराध्यक्ष पद आरक्षित है. चिमूर नगर पालिका में 10 प्रभाग में 20 पार्षद होंगे. 22557 मतदाताओं में 11392 महिला और 11165 पुरूष मतदाता है. यहां अनुसूचित जाति महिला के लिए नगराध्यक्ष पद आरक्षित है. एकमात्र भिसी नगरपंचायत में 17 प्रभाग में 17 पार्षद होंगे. 8942 मतदाताओं में 4458 महिला और 4484 पुरूष मतदाता होंगे. यहां अनुसूचित जाति सामान्य के लिए नगराध्यक्ष पद आरक्षित है.